भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 685

उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई, 2026

बजट का उपयोग

685. श्री कीर्ति आज़ाद:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बजट आवंटनों के कम उपयोग के क्या कारण हैं और जिसके तहत

बीएसएनएल/एमटीएनएल पुनरुद्धार योजना के लिए आवंटित निधि का केवल 6 प्रतिशत, भारतनेट के लिए 23 प्रतिशत और भारतीय रेलवे के लिए कनेक्टिविटी (सीआईओआर) योजना के लिए केवल 8 प्रतिशत ही व्यय किया गया;

(ख) कम उपयोग के संबंध में स्थायी समिति की बार-बार की टिप्पणियों के बाद शुरू की गई परियोजना की समय-सीमा क्या है और उल्लेखनीय उपलब्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या विभाग ने उक्त टिप्पणियों के बाद से कोई जोखिम-आधारित या प्रदर्शन से संबंधित बजट निगरानी तंत्र क्रियाशील किया है और यदि हां, तो इन तंत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर)

(क) वित्त वर्ष 2024-25 में, संशोधित प्राक्कलन (आरई) की तुलना में निधिओं का उपयोग बीएसएनएल/एमटीएनएल पुनरुद्धार योजना में 99.87 प्रतिशत, भारत नेट में 61.46 प्रतिशत और स्पूफड इनकमिंग इंटरनेशनल कॉल सिस्टम (सीआईओआर) की रोकथाम में 72.06 प्रतिशत था।

भारत नेट के संबंध में वित्त वर्ष 2024-25 में निधियों के 61.46 प्रतिशत उपयोग का कारण बीएसएनएल, जो एबीपी के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी है, द्वारा संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) के कार्यान्वयन के लिए बोलियों को अंतिम रूप देने में बिलंब होना है।

(ख) देश में सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए चरणबद्ध तरीके से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के प्रावधान के लिए भारतनेट कार्यक्रम को अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, सरकार ने भारतनेट के चरण-I और II के अंतर्गत सृजित मौजूदा नेटवर्क का उन्नयन करने और शेष ग्राम पंचायतों और शेष ग्राम पंचायत विहीन गावों के लिए कनेक्टिविटी के लिए वृद्धिशील नेटवर्क बनाने के लिए ऑन-डिमांड आधार पर पांच घरेलू फाइबर इंटरनेट कनेक्शनों की न्यूनतम मांग के साथ 10 वर्षों के लिए प्रचालन और अनुरक्षण और 1.5 करोड़ होम फाइबर इंटरनेट कनेक्शनों के प्रावधान के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को अनुमोदित किया है। जून 2026 के दौरान, 80,472 ग्राम पंचायतों में भारतनेट प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) चालू हैं।

(ग) विभाग ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म *अर्थात* सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और व्यय और निधि उपयोग की निगरानी के लिए ईलेखा का उपयोग कर रहा है। निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के संबंध में वास्तविक और वित्तीय प्रगति की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

****